25 OCT 2010 दै. स्वदेश, भोपाल

सपनों में भरें रंग

खजुराहो समिट के संकल्पों को साकार करने की जरूरत

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आयोजित खजुराहो इन्वेस्टर्स मीट की सफलता ने एक बार फिर राज्य के सपनों को पंख लगा दिए हैं। राज्य की सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान की यह बड़ी सफलता है कि 2.35 लाख करोड़ के करारों के साथ समिट का समापन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर बहुत महत्व की बात कही कि इन करारों को कागज का टुकड़ा न समझा जाए। यदि उद्योगपति गंभीर न होंगें तो सरकार भी इन कागज के टुकड़ों का बोझ नहीं उठाएगी। दूसरी बात मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कही कि निवेश की सुविधाओं के बदले निवेशकों को कुछ और नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहां सरकार के द्वारा फंड लेने का फंडा भी नहीं है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की नीयत और घोषणाएं दोनों प्रसंशायोग्य हैं। वे वास्तव में सच्चे मन से राज्य को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। कुळ 107 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर बताते हैं कि सरकार ने इसके लिए गंभीर होमवर्क भी किया होगा और उसके इरादे बहुत साफ हैं। सन 2012 में जब अगली इन्वेस्टर्स मीट होगी,तब तक सरकार एक लंबा रास्ता तय कर चुकी होगी। उस समय तो वादों की हकीकत भी सामने होगी और आगे बढ़ने की दिशा भी तय हो चुकी होगी। राज्य की भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री में एक आत्मविश्वास है जिसने इन प्रक्रियाओं को ताकत दी है। समिट में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की उपस्थिति और उनके द्वारा पांच साल में 75 हजार करोड़ का निवेश करने की घोषणा वास्तव में उत्साह जनक है। यह निवेश बिजली और सीमेंट के क्षेत्र में किया जाना है। समिट में केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री अरूण यादव ने जहां केंद्र की तरफ से हर तरह की मदद का आश्वासन दिया वहीं उनका यह सुझाव भी महत्व का है कि मप्र सरकार को अपना कर ढांचा दुरूस्त करना चाहिए और इससे निवेश भी बढेगा। जाहिर तौर पर अगर अरूण यादव का सुझाव गौर करने योग्य है तो सरकार को इस पर ध्यान देते हुए उचित कदम उठाने चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश अपनी राजनीतिक स्थिरता और सब प्रकार के मानव और खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद उद्योगपतियों की बेहतर पसंद नहीं रहा है। इस वातावरण को बदलने की जरूरत है। शांतिपूर्ण राज्य, राजनीतिक स्थिरता, दो दलीय व्यवस्था,अपार मानव संसाधन की उपलब्धता ऐसे शुभसंकेत है जो औद्योगिक विकास के लिए जरूरी हैं। इसके बाद भी हमारी प्रगति पर ग्रहण लगे हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारी पहचान एक पिछड़े राज्य के रूप में है। इसे तेजी से बदलने की जरूरत है। यह भी महत्व की बात है कि शिवराज सिंह चौहान के रूप में राज्य के पास एक ऐसा युवा नेतृत्व है जो मध्यप्रदेश के सपनों को सच करने की जिम्मेदारी के साथ काम करते दिख रहे हैं। हमें सरकार और उसके मुखिया के संकल्पों को जमीन में उतारने के लिए आगे आना होगा। सामाजिक सहकार और सहभाग के बिना मप्र को सफलताएं नहीं मिल सकतीं। हर क्षेत्र में विकास के लिए सबको हाथ लगाना होगा। इससे राज्य को निश्चय ही अलग और विशिष्ट पहचान मिलेगी।